Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY

CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 31-05-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Saturday, 31 May, 2025

Editin : Internatinal Table f Cntents

Page 01 **Syllabus : GS 3 : Indian Ecnmy**	जीडीपी की वृद्धि 6.5%, महामारी के बाद से सबसे धीमी है
Page 03 **Syllabus : GS 2 & 3 : Gvernance & Envirnment**	नई पनबिजली परियोजनाओं के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन
Page 03 **Syllabus : GS 2 : Internatinal relatins**	रक्षा, सुरक्षा मामलों पर भारत के साथ मिलकर काम करना: न्यूजीलैंड के डिप्टी पीएम
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Gvernance**	पुनर्निर्माण J & K: नागरिकों को गोलाबारी से उबरने के लिए शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है
Page 07 **Syllabus : GS 2 : Gvernance**	एक नौ साल का बंधुआ मजदूर
Page 06 : Editrial Analysis: **Syllabus : GS 2 : Gvernance & Scial Justice**	केवल छात्रों को नामांकित नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें कौशल से लैस करते हैं

Page 01 : GS 3 : Indian Ecnmy

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की अनंतिम जीडीपी वृद्धि 6.5% आंकी गई है, जो महामारी वर्ष (2020-21) के बाद से सबसे धीमी गति है। जबकि चौथी तिमाही की वृद्धि दर बढ़कर 7.4% हो गई, यह पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में दर्ज 8.4% से कम है। मजबूत तिमाही आंकड़ों के बावजूद यह मंदी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक और वैश्विक चुनौतियों को दर्शाती है।

GDP growth at 6.5%, the slowest since pandemic

Though real GDP growth in Q4 accelerated to 7.4%, the fastest quarterly growth in 2024-25, it was still slower than 8.4% in Q4 of the previous fiscal; quarterly GDP growth in Q3 stood at 6.4%

T.C.A. Sharad Raghavan
NEW DELHI

While a significant uptick in economic activity in the fourth quarter (Q4) of financial year 2024-25 pushed Gross Domestic Product (GDP) growth for the full year to 6.5%, as per the provisional estimates for 2024-25 released by the government on Friday, this is the slowest since the pandemic year 2020-21.

As per data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, real GDP growth in Q4 of 2024-25 accelerated to 7.4%, the fastest quarterly growth in the year. It was still slower than 8.4% growth seen in Q4 of the previous financial year. Quarterly GDP growth in Q3 stood at 6.4%.

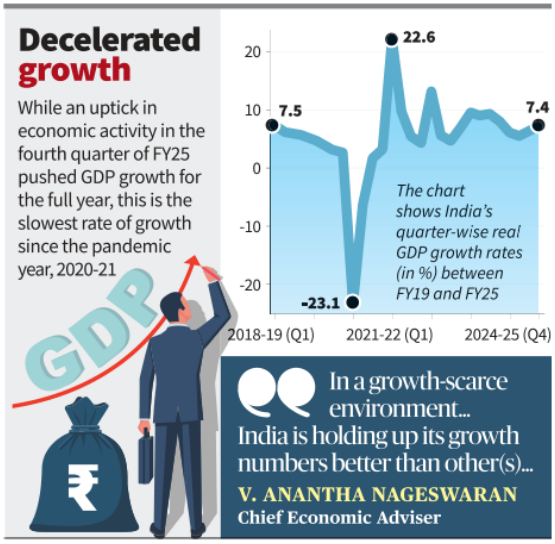

Source: MOSPI, India

'India held its own'

Chief Economic Adviser V. Anantha Nageswaran, in a press briefing following the release of the data, sought to downplay the post-COVID slowdown of the economy, saying that India has held its own in a "growth-scarce" global environment. "If you look in real terms, India's growth rate differential in comparison to the average growth rate of advanced economies was on the lower side during the 'boom era' between 2003 and 2010," Mr. Nageswaran explained. "The growth differential post-COVID is higher than the growth differential in the 'boom era'." "In other words, in a growth-scarce environment post COVID and despite the rising uncertainties due to political conflicts and trade tensions, India is holding up its growth numbers better than many advanced economies," he added.

The agriculture sector continued its strong performance in Q4, leading to a relatively strong showing for the full year. The manufacturing sector's growth stood at 4.8% in Q4 of FY25, the second fastest quarterly growth in the year, on a high base of 11.3% in Q4 of the previous year. The sector grew 4.5% in the full financial year 2024-25 The construction sector returned to double-digit growth of 10.8% in the fourth quarter, the fastest in the year, and faster than the 8.7% seen in Q4 of 2023-24. The sector's full-year growth stood at 9.4% in 2024-25, down from 10.4% in 2023-24.

The data released on Friday showed that growth in household consumption quickened to 7.2% in 2024-25 from 5.6% in the previous year.

आर्थिक प्रदर्शन के प्रमुख मुख्य आकर्षण:

1. त्रैमासिक विकास के रुझान:

- Q4 FY25: 7.4% (वर्ष के लिए उच्चतम लेकिन पिछले वर्ष के Q4 से नीचे)
- Q3 FY25: 6.4% यह वर्ष के उत्तरार्ध में एक ऊपर की ओर प्रक्षेपवक्र दिखाता है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष से एक मॉडरेशन का संकेत देता है।

2. सेक्टोरल इनसाइट्स:

- कृषि: समग्र स्थिरता का समर्थन करते हुए, एक सुसंगत कलाकार बने रहे।
- विनिर्माण: Q4 में 4.8% की वृद्धि हुई, FY24 के Q4 में 11.3% के उच्च आधार के बावजूद, लचीलापन लेकिन धीमी गति का सुझाव दिया।
- निर्माण: Q4 (10.8%) में मजबूत दोहरे अंकों की वृद्धि देखी गई, जो बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाली मांग का संकेत देती है, हालांकि वार्षिक वृद्धि 10.4%से 9.4%तक धीमी हो गई।

3. निजी खपत:

- घरेलू खपत में वृद्धि पिछले वर्ष में 5.6% से 7.2% तक सुधार हुई - घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण संकेत, विशेष रूप से वश में निर्यात और वैश्विक अनिश्चितता के परिदृश्य में।

4. सरकारी दृष्टिकोण:

- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी। अनंत नजवरन ने वैश्विक हेडविंड, पोस्ट-कोविड अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनावों का हवाला देते हुए मंदी का बचाव किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत का विकास अंतर अब 2003-2010 के बूम युग के दौरान अधिक है, जो "ग्रोथ-स्केयर" दुनिया में भारत की सापेक्ष शक्ति को प्रदर्शित करता है।

महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- ताकत की जेब के साथ विकास की मंदी: जबकि हेडलाइन संख्या पिछले वर्षों की तुलना में कम है, मजबूत Q4 आंकड़े और बेहतर उपभोग का सुझाव है कि घरेलू वसूली चल रही है। फिर भी, विनिर्माण और निर्यात कमजोरियां महत्वपूर्ण बाधाएं बनी हुई हैं।
- वैश्विक संदर्भ मामले: भू-राजनीतिक संघर्ष, संरक्षणवाद, और मुद्रास्फीति के दबाव द्वारा चिह्नित अवधि में, भारत की 6% से अधिक वृद्धि को बनाए रखने की क्षमता इसे बेहतर प्रदर्शन वाली बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच रखती है।
- सुधारों की आवश्यकता: मंदी का संकेत आपूर्ति-पक्ष सुधारों, श्रम बाजार के लचीलेपन और एमएसएमई के लिए समर्थन की आवश्यकता है, विशेष रूप से विनिर्माण में, दीर्घकालिक गति को बनाए रखने के लिए।
- ग्रामीण बनाम शहरी विभाजन: कृषि और निर्माण क्षेत्रों में वृद्धि ग्रामीण और अर्ध-शहरी मांग को दर्शाती है, जबकि शहरी-केंद्रित विनिर्माण और सेवाओं को नए सिरे से नीतिगत ध्यान की आवश्यकता होती है।
- नीतिगत निहितार्थ: राजकोषीय नीति को विकास-सहायक लेकिन विवेकपूर्ण रहना चाहिए, और सरकार को विकास की अनिवार्यता के साथ मुद्रास्फीति की चिंताओं को संतुलित करना चाहिए, विशेष रूप से आगामी चुनावों और बाहरी दबावों के साथ।

UPSC Mains Practice Questin

प्रश्न: 2024-25 **के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर महामारी के बाद से सबसे धीमी रही है, फिर भी यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन को दर्शाती है। इस संदर्भ में, चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालकों और बाधाओं का विश्लेषण करें। साथ ही, सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उपाय सुझाएँ। (250 wrds)**

Page 03 : GS 2 & 3 : Gvernance & Envirnment

अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों, खास तौर पर सियांग, ड्रि और लोहित नदी घाटियों में मेगा-बांधों के खिलाफ, ने जलविद्युत विकास, आदिवासी अधिकारों, पारिस्थितिकी भेद्यता और सांस्कृतिक विरासत के बारे में चिंताओं को फिर से जगा दिया है। यह उभरता हुआ प्रतिरोध राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और स्थानीय पर्यावरणीय-सामाजिक चिंताओं के बीच संघर्ष को दर्शाता है, जो इसे शासन और पर्यावरण नीति चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाता है।

Protests spread in Arunachal Pradesh against new hydroelectric projects

The Hindu Bureau
GUWAHATI

An intense opposition to a proposed mega-dam in the Siang River belt has set off a chain of protests against other hydropower projects in Arunachal Pradesh.

A society representing several villages wrote to the Dibang Valley district authorities on May 29, voicing its "strong and reasoned objection" to the 400 megawatt Mihundo (Mihumdon) Hydroelectric Project proposed on the Dri River. Scheduled to be commissioned in 2026, this run-of-the-river project was assigned to the Satluj Jal Vidyut Nigam.

The Ekhomey Mowo Welfare Society, based in Anini, the district headquarters, said the project was illegal as the mandatory free, prior, and informed consent was not obtained from the Gram Sabha or the residents of Angrim Valley who would be affected.

Opposition to the projects was triggered by protests against the proposed mega-dam in the Siang River belt. SPECIAL ARRANGEMENT

The society's general secretary, Morey Molo, and treasurer Aisi Mow underlined the district's seismic and ecological vulnerability, asserting that the locals "do not want dam-based development on our ancestral lands".

Opposition to the Dri River project came a day after residents of the remote Nukung and Mla villages voiced their resistance to the proposed 1200 MW Kalai-II Hydroelectric Project on the Lohit River in Anjaw district during a public consultation and social impact assessment review.

According to the social impact assessment report prepared by the GB Pant National Institute of Himalayan Environment, Nukung and Mla villages would be severely affected by the project.

In a letter to the Anjaw Deputy Commissioner, the Nukung Welfare Society said that the project was unacceptable to the indigenous communities in the area.

"The total obliteration of our ancestral land by a project we did not consent to is unacceptable and illegal," Roshan Tawsik, the society's chairman, said.

The villagers pointed out that the potential submergence of sacred Mishmi tribal cultural and spiritual sites by the mega-dam was of particular concern. These sites include Kutung Graam, the abode of the community's supreme deity and Parshuram Kund downstream.

Meanwhile, the Siang Indigenous Farmers' Forum vowed to intensify its agitation against the proposed 11,000 MW Siang Upper Multi-purpose Project and the "militarisation" of the targeted sites along the Siang River.

The government has been pushing this project to be executed by the NHPC, arguing that it would help minimise the adverse impact of a 60,000 MW hydroelectric project China has been planning on the Yarlung Tsangpo River upstream.

प्रमुख घटनाक्रम:

1. ट्रिगरिंग घटना: 11,000 मेगावाट की सियांग अपर मल्टीपर्पज परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं तक फैल गया है। इस विशेष परियोजना को सरकार द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि चीन यारलुंग त्सांगपो अपस्ट्रीम पर 60,000 मेगावाट की पनबिजली परियोजना बनाने की योजना बना रहा है, जिससे पानी के बहाव के बढ़ने की आशंका बढ़ गई है।

2. पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन:

दिबांग घाटी: एकहोमी मोवो वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 400 मेगावाट की मिहुंडो (मिहुमदोन) पनबिजली परियोजना का विरोध स्थानीय ग्राम सभाओं की सहमति की कमी, पीईएसए अधिनियम के उल्लंघन और भूकंपीय जोखिम पर केंद्रित है।

अंजॉ जिला: 1200 मेगावाट की कलाई-II परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नुकसान को उजागर करता है, जिसमें कुटुंग ग्राम और परशुराम कुंड जैसे स्थल शामिल हैं - जो मिश्मी जनजाति के लिए पवित्र हैं।

3. कानूनी और नैतिक चिंताएँ: ग्रामीणों का तर्क है कि कोई स्वतंत्र, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) प्राप्त नहीं की गई थी, जो अनुसूची VI, वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत संवैधानिक अधिकारों और UNDRIP (स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा) के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन है।

4. पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक संवेदनशीलता:

- अरुणाचल प्रदेश एक नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, जो भूस्खलन, भूकंप और जैव विविधता के नुकसान का खतरा है।
- स्वदेशी समुदाय इस बात पर जोर देते हैं कि पैतृक भूमि और पवित्र स्थल केवल संपत्ति नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक निरंतरता के भंडार हैं।
- 5. रणनीतिक और राष्ट्रीय हित आयाम: सरकार का यह कदम रणनीतिक चिंताओं से प्रेरित है, विशेष रूप से ऊपरी ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्संगपो) पर चीनी पनबिजली योजनाओं का प्रतिकार करने के लिए, राष्ट्रीय जल सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का हवाला देते हुए।

महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- विकास बनाम अधिकार संघर्ष: बार-बार होने वाला संघर्ष शासन की एक गहरी चुनौती को दर्शाता है - जनजातीय अधिकारों और पारिस्थितिक अखंडता को कम किए बिना ऊर्जा लक्ष्यों का पीछा करना। "राष्ट्रीय हित" के नाम पर अक्सर कानूनी सुरक्षा उपायों को दरकिनार कर दिया जाता है।
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) दोष: अनिवार्य होने के बावजूद, एसआईए अक्सर एक टिक-बॉक्स अभ्यास बनकर रह जाता है। वास्तविक, सहभागी परामर्श आयोजित करने में विफलता विश्वास को खत्म करती है और प्रतिरोध को जन्म देती है।
- नीतिगत अंतराल: जबकि भारत के पास महत्वाकांक्षी जलविद्युत लक्ष्य हैं, विशेष रूप से स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए, ऐसी परियोजनाओं में स्वदेशी भागीदारी के लिए एक व्यापक ढांचे की कमी स्पष्ट है।
- विकल्पों की आवश्यकता: मेगा-बांधों के बजाय, सरकार को नाजुक इलाकों के अनुकूल विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा, माइक्रो-हाइड्रो और सौर ऊर्जा की खोज करनी चाहिए, जो स्थिरता को समावेश के साथ संरेखित करे।

UPSC Mains Practice Questin

प्रश्न: उत्तर-पूर्व में जलविद्युत परियोजनाएँ भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, लेकिन स्थानीय समुदायों में इनके कारण व्यापक विरोध हुआ है। ऐसी परियोजनाओं के पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और रणनीतिक आयामों की आलोचनात्मक जाँच करें। इन विवादों को हल करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण सुझाएँ। (250 Wrds)

Page : 03 : GS 2 : Internatinal relatins

न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान अपने देश की विदेश नीति में रणनीतिक बदलाव पर प्रकाश डाला - जो भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने का संकेत है। बढ़ती भू-राजनीतिक अस्थिरता की पृष्ठभूमि में, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ न्यूजीलैंड की नई भागीदारी इसकी पारंपरिक रूप से प्रशांत-केंद्रित कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

Working closely with India on defence, security matters: New Zealand Deputy PM

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

In the current era of "great uncertainty", New Zealand has started working "more closely" with India in the fields of defence and security, said Winston Peters, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of New Zealand here on Friday.

Speaking at an event, Mr. Peters gave an overview of his country's foreign policy, and said that freedom of navigation in the Indo-Pacific region is "crucial" for New Zealand.

"During a time of great uncertainty, instability and disorder, we have taken steps to work more closely on matters of defence and security with India. A recently signed Defence Cooperation Arrangement will facilitate closer links between our militaries," Mr. Peters said, speaking at a fireside chat organised by the Ananta Aspen Centre.

Winston Peters

Mr. Peters, who was among the global leaders who had joined India in condoling the loss of lives in the April 22 terror attack in Pahalgam, said that security cooperation between the two sides is increasing. "The New Zealand Navy is leading Combined Task Force 150, charged with securing trade routes and countering terrorism, smuggling, and piracy in the Indian Ocean and Gulf of Aden," he added.

To deal with the uncertain and unpredictable conditions in the fields of security and economy, New Zealand has "reset" its foreign policy and is "significantly increasing" its "focus and resources" on South and South-east Asia, Mr. Peters said. Describing India as a "geopolitical giant", he said that India has emerged as an "indispensable security actor in both regional and global spheres. In the prevailing international circumstances, he argued in favour of giving space to diplomacy.

"Since war and instability is everyone's calamity, diplomacy is the business of us all. We have observed that at this moment in time the ability to talk with, rather than at, each other has never been more needed," Mr. Peters said, arguing in favour of safeguarding rights of countries like New Zealand that he described as a "small state".

मुख्य बिंदु:

1. रक्षा सहयोग समझौता: हाल ही में हस्ताक्षरित रक्षा सहयोग व्यवस्था (DCA) भारत और न्यूजीलैंड के बीच सैन्य संबंधों को बढ़ाएगी। यह कदम इंडो-पैसिफिक में न्यूजीलैंड की पारंपरिक कम सैन्य भागीदारी से अलग है और भारत को एक प्रमुख सुरक्षा भागीदार के रूप में मान्यता देता है।

2. नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री सुरक्षा: न्यूजीलैंड ने अपने व्यापार और आर्थिक हितों के लिए विशेष रूप से इंडो-पैसिफिक में सुरक्षित समुद्री मार्गों के महत्व पर जोर दिया। न्यूजीलैंड की नौसेना संयुक्त टास्क फोर्स 150 (हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में आतंकवाद, समुद्री डकैती और तस्करी पर केंद्रित) का नेतृत्व कर रही है, भारत के साथ सहयोग साझा समुद्री सुरक्षा उद्देश्यों को बढ़ाता है।

3. भारत एक "भूराजनीतिक दिग्गज" के रूप में: पीटर्स ने क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में भारत के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार किया, इसे "अपरिहार्य सुरक्षा अभिनेता" कहा। यह मान्यता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्वाड, आईओआर सुरक्षा वास्तुकला और वैश्विक दक्षिण साझेदारी में इसकी बढ़ती भूमिका के अनुरूप है।

4. न्यूजीलैंड का रणनीतिक रीसेट: बढ़ती अनिश्चितता और बदलती वैश्विक शक्ति गतिशीलता के जवाब में, न्यूजीलैंड एशिया, विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया पर कूटनीतिक, आर्थिक और रक्षा फोकस का विस्तार कर रहा है। इसमें बहुपक्षीय जुड़ाव और द्विपक्षीय सहयोग दोनों शामिल हैं, जिसमें भारत मुख्य है।

5. शांति के लिए एक उपकरण के रूप में कूटनीति: श्री पीटर्स ने संवाद-आधारित संघर्ष समाधान की पुरजोर वकालत की, छोटे राज्यों को अलगाववाद के बजाय सामूहिक कूटनीति के माध्यम से अपनी स्वायत्तता की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- न्यूजीलैंड के भू-राजनीतिक रुख में बदलाव: परंपरागत रूप से तटस्थ और प्रशांत पर केंद्रित, भारत के साथ न्यूजीलैंड का बढ़ता रणनीतिक अभिसरण चीन की मुखरता, क्षेत्रीय व्यवधान और गठबंधनों की वैश्विक पुनर्व्यवस्था की प्रतिक्रिया है।
- भारत की विस्तारित इंडो-पैसिफिक भूमिका: यह विकास भारत की खुद को एक विश्वसनीय समुद्री और रणनीतिक शक्ति के रूप में पेश करने में सफलता को दर्शाता है, जो विशेष रूप से हिंद महासागर में चीन के नौसैनिक विस्तार और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सामने क्षेत्रीय सुरक्षा हितों को संतुलित करने में सक्षम है।
- पारस्परिक हित: दोनों देश नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सुरक्षित समुद्री कॉमन्स, जलवायु सहयोग और आतंकवाद-रोधी उपायों में रुचि रखते हैं। बढ़ा हुआ रक्षा सहयोग शिक्षा, व्यापार और प्रवासी संबंधों में बढ़ते संबंधों का पूरक है।

आगे की चुनौतियाँ:

- रणनीतिक इरादे के बावजूद, न्यूजीलैंड की सैन्य क्षमताओं और भौगोलिक दूरी का सीमित पैमाना ठोस परिणामों को सीमित कर सकता है। हालाँकि, समुद्री जागरूकता, संयुक्त अभ्यास और बहुपक्षीय मंचों में निरंतर सहयोग से दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं।

निष्कर्ष:

- भारत के लिए न्यूजीलैंड की रणनीतिक पहुँच इंडो-पैसिफिक में मध्य-शक्ति सहयोग के एक नए युग को रेखांकित करती है। भारत के लिए, यह एक क्षेत्रीय स्थिरता और एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में इसके उभरने की पुष्टि करता है। आगे बढ़ते हुए, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ एक संतुलित, समावेशी और नियम-आधारित जुड़ाव भारत की समुद्री कूटनीति को मजबूत करेगा और विकसित हो रहे इंडो-पैसिफिक सुरक्षा वास्तुकला में इसकी स्थिति को मजबूत करेगा।

UPSC Mains Practice Questin

प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीति में बढ़ती अनिश्चितता के साथ, न्यूजीलैंड जैसे देश भारत के साथ घनिष्ठ रक्षा संबंध बना रहे हैं। भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण और समुद्री कूटनीति के लिए ऐसी साझेदारी के रणनीतिक महत्व का परीक्षण करें। (250 Wrds)

Page 06 : GS 2 : Gvernance

ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में सीमा पार से की गई गोलाबारी से जम्मू-कश्मीर में, खास तौर पर पुंछ, उरी, कुपवाड़ा, बारामुल्ला और राजौरी में बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। यह घटना सीमावर्ती आबादी की भेद्यता, मजबूत नागरिक सुरक्षा तंत्र की आवश्यकता और संघर्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में राहत को दीर्घकालिक विकास के साथ एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करती है।

मुख्य बिंदु:

1. नागरिक क्षति और बुनियादी ढांचे को नुकसान:

- कम से कम 1,500 घर क्षतिग्रस्त हुए (पुंछ में 690, उरी में 534)।
- 18 नागरिक मारे गए, जिसमें पुंछ सबसे अधिक प्रभावित हुआ।
- सीमावर्ती जिलों में आवासीय और सामुदायिक बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा।

2. सरकारी प्रतिक्रिया:

- केंद्रीय गृह मंत्री के प्रभावित क्षेत्रों के दौरे ने राजनीतिक आश्वासन और प्रतीकात्मक समर्थन प्रदान किया।
- पीड़ितों के परिवारों को नौकरी के पत्र वितरित करने का उद्देश्य आर्थिक राहत और मनोबल की बहाली है।
- राहत पैकेज पाइपलाइन में है, हालांकि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹1.2 लाख मुआवजे की आलोचना अपर्याप्त के रूप में की गई है।

Rebuilding J&K

Civilians need physical and economic security to recover from the shelling

Jammu and Kashmir bore the brunt of Pakistan's response to Operation Sindoor, and Union Home Minister Amit Shah rightly focused on both security and development during his visit to Poonch, where residential areas were hit by shelling from across the border. A comprehensive relief package is planned alongside the construction of more underground shelters for civilians. The J&K government is still in the process of assessing damages, but Poonch was by far the worst-affected district. A preliminary report submitted by a committee set up by the BJP to the Ministry of Home Affairs identified 1,500 houses – 690 in Poonch and 534 in Uri – that were damaged in the indiscriminate shelling. At least 18 civilians – 14 in Poonch alone – lost their lives. Pakistani shelling hit towns in Poonch, Baramulla, Kupwara and Rajouri, and the damage to civilian infrastructure was considerable. Mr. Shah on Friday visited the affected regions, expressed solidarity with the people, and handed out job appointment letters to the kin of those who lost their lives. Earlier, the Leader of the Opposition, Rahul Gandhi, and representatives of the Trinamool Congress visited the victims.

These border residents felt heard, their sense of fear dissipated to some extent, and their morale boosted by these visits. The Indian Army's statement on the India and Pakistan ceasefire "not having an expiry date" is reassuring for the border residents. Life is limping back to normalcy with residents returning to their homes, many of them shattered by the shelling. The J&K government is struggling to meet the demands of the affected population. This was evident from the relief amount approved up to ₹1.2 lakh to fully damaged houses. The affected and displaced residents described it as "insufficient" for them to return to their once-concrete and multi-storey houses. Against this backdrop, Mr. Shah's promise of a relief package is a ray of hope. Around 9,500 bunkers – 8,000 in the Jammu division and 1,500 in the Kashmir Valley – have been built by the Centre so far. However, there is a growing demand for individual bunkers in sparsely located populations in border areas of J&K, especially in the Kashmir Valley, to ensure civilians manage to shift to safer locations immediately in case of shelling by Pakistan. The Centre and the elected government in J&K should work in tandem to help border residents who are in distress.

3. सुरक्षा उपाय और नागरिक सुरक्षा:

- सक्रिय नागरिक सुरक्षा के हिस्से के रूप में 9,500 भूमिगत बंकरों (जम्मू में 8,000, कश्मीर में 1,500) का निर्माण।
- व्यक्तिगत बंकरों की बढ़ती मांग, खासकर कश्मीर घाटी के कम आबादी वाले और दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में।

4. मनोवैज्ञानिक प्रभाव और राजनीतिक पहुंच:

- राहुल गांधी और टीएमसी प्रतिनिधियों सहित विपक्षी नेताओं के दौरे ने द्विदलीय एकजुटता का संदेश दिया।
- सेना का यह बयान कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष विराम की "कोई समाप्ति तिथि नहीं है" ने निवासियों को मनोवैज्ञानिक आश्वासन दिया।

महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- सुरक्षा-विकास संबंध: सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को साथ-साथ चलना चाहिए। घरों का पुनर्निर्माण ही पर्याप्त नहीं है; सरकार को समग्र सुधार सुनिश्चित करने के लिए आजीविका सुरक्षा, आघात परामर्श, शिक्षा निरंतरता और कृषि सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।
- राहत उपायों की अपर्याप्तता: प्रस्तावित मुआवजा बहुत अपर्याप्त है, खासकर बहुमंजिला कंक्रीट घरों के लिए, जो संदर्भ-संवेदनशील राहत योजना की आवश्यकता को दर्शाता है। क्षति की सीमा और स्थानीय निर्माण मानदंडों के आधार पर एक श्रेणीबद्ध मुआवजा नीति अपनाई जानी चाहिए।
- नागरिक सुरक्षा बुनियादी ढांचे में कमी: हालांकि बंकरों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनका वितरण असमान है, और सीमावर्ती बस्तियों की बिखरी प्रकृति के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा समाधान आवश्यक हैं। वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली, सामुदायिक अभ्यास और निकासी प्रोटोकॉल को भी संस्थागत बनाया जाना चाहिए।
- संघीय-राज्य समन्वय: जम्मू-कश्मीर में चल रहे राजनीतिक परिवर्तन के साथ, समय पर सहायता वितरण, राहत योजनाओं के कार्यान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं की बहाली के लिए प्रभावी केंद्र-यूटी समन्वय आवश्यक है।
- दीर्घकालिक शांति रणनीति की आवश्यकता: इस तरह की गोलाबारी की घटनाएं हमें पाकिस्तान के साथ नाजुक युद्धविराम व्यवस्था की याद दिलाती हैं। भारत को तनाव को बढ़ने से रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सैन्य तैयारियों और कूटनीतिक चैनलों दोनों में निवेश करना चाहिए।

निष्कर्ष:

- जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के पुनर्निर्माण को राहत-केंद्रित अभ्यास तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक पुनर्वास और भावनात्मक उपचार को एकीकृत करता है। केंद्र और जम्मू-कश्मीर के स्थानीय प्रशासन को प्रभावित निवासियों के लिए विश्वास, सम्मान और सुरक्षा बहाल करने के लिए निर्णायक और सहयोगात्मक रूप से कार्य करना चाहिए। तभी इस भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थायी शांति और लचीलापन हासिल किया जा सकता है।

UPSC Mains Practice Questin

प्रश्न: सीमा पार शत्रुता के मद्देनजर, सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा और आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित करना सैन्य तैयारी जितना ही महत्वपूर्ण है। जम्मू और कश्मीर में हाल की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा करें। (250 wrds)

Page 07: GS 2 : Gvernance

तमिलनाडु में बंधुआ मजदूरी के लिए काम करते समय कथित तौर पर ऋण के लिए जमानत के तौर पर रखे गए नौ वर्षीय वेंकटेश की दुखद मौत, भारत में बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के निरंतर प्रचलन को उजागर करती है, खासकर यानाडी जैसे कमजोर आदिवासी समुदायों के बीच। बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 जैसे मजबूत कानूनी ढांचे के अस्तित्व के बावजूद, ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के कुछ हिस्सों में यह प्रथा बेरोकटोक जारी है, जो कानून प्रवर्तन, पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती है।

Mannepalli Ankamma holds her employer's daughter. Ankamma's nine-year-old son was taken away from her as 'collateral' for a debt and was later found dead. G.N. RAO

A nine-year-old bonded labourer

Last week, a duck farmer was arrested on charges of keeping a child from Andhra Pradesh as 'collateral' for a loan and then killing him in Tamil Nadu. Though bonded labour has long been banned by law, it continues to be practised, say activists. **Nellore Sravani** reports on how the boy's mother, Ankamma, a woman from a tribal community, tried in vain to bring her child back home

Two years ago, Mannepalli Ankamma, a woman from a tribal community in Andhra Pradesh, who does not know her age, decided to work for N. Muthu, a 60-year-old duck farmer. He promised her a salary of ₹24,000 a month for herding cows and helping him run a sweet shop in Satyavedu, a town in the Tirupati district of Andhra Pradesh. Ankamma took an advance of ₹15,000 from him. When she was unable to repay the amount, Muthu took away her youngest son, M. Venkatesh, as 'collateral'. He also allegedly inflated the amount she owed him to ₹42,000.

On April 9, Ankamma spoke to Venkatesh over the phone. The nine-year-old boy told her that he was busy tending to Muthu's ducks in Kancheepuram district in Tamil Nadu. Ankamma lives in Thurakapalle village in Duttaluru mandal of Nellore district in Andhra Pradesh, where she works in her current employer Siva Reddy's lemon orchard. She assured her child that she would be there in two days with ₹42,000 of cash in hand. She promised that he would be home soon.

Before ending the call, Ankamma asked Venkatesh what he had eaten for lunch. Curd-rice, he said, an improvement over the previous day's meal of rice mixed with water.

That was the last time Ankamma spoke to him.

Buried by the river

A week later, clutching wads of cash, Ankamma travelled to Satyavedu, about 270 kilometres from her village. But Muthu refused the money.

"He used casteist slurs against me," she recalls. "He also told me that my son had run away with his phone and some cash." Dejected, Ankamma returned home.

When a month passed and there was still no word from Venkatesh, Reddy helped her file a First Information Report (FIR) at the Satyavedu police station on May 19.

The police began their investigation. On being questioned, Muthu told them that Venkatesh had died of jaundice on April 12 at a private hospital at Pudupalayam in Tiruvannamalai district of Tamil Nadu. He confessed that he had buried the boy near the Palar river.

The police found Venkatesh's decomposed body and informed Ankamma. "I knew it was him. He was wearing a vest and shorts. I knew it was my boy though he had become unrecognisable," says Ankamma, her cheeks wet with tears.

While the medical officer from the Chengalpattu Government Medical College declined to share the post-mortem report, the Puttur police quoted the report and said that the stated cause of death was "blunt force injury to the head by (a) heavy weapon". The injuries were "sufficient to cause death in ordinary course of nature".

At first, Muthu, his wife, and son were arrested under the provisions of the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976; the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986; the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2016; and the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

On May 24, Deputy Superintendent of Police G. Ravi Kumar, who probed the case, said Section 103 (1) (murder) under the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, was also added to the FIR.

Bonded labour is a system where creditors force debtors to repay debts through labour. The Act prohibits any person from making advances under, or in pursuance of, the bonded labour system. It also prohibits compelling a person to render bonded or forced labour. However, the practice continues till date, say activists.

> It was my fault that I accepted a loan of ₹10,000 from a creditor. At the time, we had no work, no food, and no access to drinking water. So, I took the money
>
> KOTTAIAH
> Former bonded labourer

A debt that cost a son

Sitting on a flat rock outside Reddy's house on the outskirts of Thurakapalle village, Ankamma cries softly. Thurakapalle is 8 km from Duttaluru town. A narrow muddy pavement leads to the village. The silence of the surroundings is broken by the crowing of roosters.

Reddy's house stands in the midst of a vast expanse of lemon orchards. Ankamma and her husband Prakash get paid ₹15,000 a month for taking care of Reddy's 12-acre orchard, tending to 10 buffaloes, and doing other odd jobs for him.

Ankamma and Prakash do not have a house. "This is home," she says, pointing to a small hut-like structure, perched precariously on four logs. The logs are covered on top by a tarpaulin sheet. There is just enough space for them to sleep.

When Reddy is around, Prakash and Ankamma sit on the ground. "They are Reddaku (Reddys). They are 'big' people," Ankamma says with a reverential tone. She believes that what happened was all her fault. "We will not leave Siva Reddy until our last breath. We had left him to work for Muthu and that is why this happened to us. From now on, we will be loyal to him."

Two years ago, Ankamma and Prakash went to work for Muthu after Ankamma's mother told her that he may pay more. Taking an advance of ₹15,000 from Muthu, they began taking his ducks for grazing. Though he promised them a salary of ₹24,000 a month, Muthu did not give them anything more than the advance amount.

The couple slept in the fields under the sky. They often stayed awake at night, fearing snakes and scorpions. They moved from place to place every week, foraging for feed. They offered to repay the debt in instalments, but Muthu refused.

Ankamma has three children from her previous marriage — Chenchu Krishna (15), Ravi Lakshmamma (12), and Venkatesh. When her first husband died last year, she and Prakash left for Guduru, near Tirupati district, for his final rites. When they did not return, an enraged Muthu went in search of them. He took Venkatesh away, saying the boy was 'collateral'.

"Everyone says we will get some cash (compensation)," says Ankamma. "But we will not demand anything except justice for my son."

The Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer - 2021 states that immediate financial assistance of up to ₹30,000 is guaranteed to individuals rescued from bonded labour. Once the accused is convicted, the aid can go up to ₹3 lakh, depending on the severity of the case.

Ravi Kumar, the administrative officer at the Revenue Divisional Officer's (RDO) office in Sullurpeta, says the Tirupati administration is considering providing a housing site and compensation to the family. Satyavedu falls under the purview of the Sullurpeta RDO.

Activists say the administration should also issue a 'release certificate' to Ankamma's family. "Release certificates can be issued only to those in bonded labour. Technically, only the boy was a bonded labourer. Since he is dead, the family is not eligible for the certificate," Kumar explains.

'Poor, unlettered, and fearful'

Andhra Pradesh is both a source and a destination State for bonded labour. "The problem is not as prevalent as it used to be, but many cases do not come to light these days. In addition to migrant labourers from Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal, and Chhattisgarh, the most marginalised locals fall prey to the system," says Ravi Sunil Kumar, convenor of the Vetti Vimochana Coalition, a group of NGOs working on bonded labour issues. According to data compiled by the group, 402 people have been rescued from bonded labour in the State from January 2023 to date. Most of them, including Ankamma, belong to the Yanadi community.

A report from the National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes, published in 2008, says the Yanadis are one of the 59 Denotified Tribes and 60 Nomadic Tribes of Andhra Pradesh. As per the 2011 Census, there were more than 5 lakh Yanadis in the composite State of Andhra Pradesh and Telangana.

Noorbasha Babavali, a research assistant at the Centre for Study of Social Inclusion at Andhra University in Visakhapatnam, says the Yanadis are extremely poor. Only 35.35% of them are lettered. "They have been exploited as they don't know about the legal system. Their fear of society keeps them away from the mainstream. They don't own any assets and stay on the canal bunds and in hilly areas." Ankamma says she did not know that *vetti chakiri* (bonded labour) is illegal.

"Many Yanadis do not open up to strangers even if they are offered help," says Ch. Venkateswarlu, a Yanadi leader from Alluru, a village near Ongole in Prakasam district. "Unlike Ankamma, others do not share their troubles. They fear being beaten up by their employers."

He recalls another incident in which two bonded labourers died of electrocution while working in a field in Palnadu district. "Though this happened a few months ago, the labourers' families still work as bonded labourers," he says.

Kotaiah's escape

Katti Kotaiah, 56, who also belongs to the Yanadi community, escaped the clutches of his employer at Chilakaluripeta town.

Kotaiah lives in a Yanadi colony at Alluru, a village near the Kothapatnam beach in Prakasam district. About 400 Yanadis live in the colony. At least 10 members live in one hut.

Like Ankamma, Kotaiah blames himself for what happened. "It was my fault that I accepted a loan of ₹10,000 from a creditor in Chilakaluripeta in Palnadu district. At the time, we had no work, no food, and no access to drinking water. So, I took the money," he says.

To repay that amount, his family of seven, including three children, had to work as bonded labourers for around 20 years. "We set out to work when my son's three children were toddlers. Now they are between 16 and 20," he says. By the time of their release last year, that debt of ₹1,500 had risen to ₹15 lakh. The family was sold more than thrice, and worked as bonded labourers under different employers, says Kotaiah.

He says their job was to cut Subabul logs, used primarily in the pulp and paper industry. He and his wife cut two tonnes of logs every day. "In a week, if we cut 14 tonnes, we would get ₹1,500," he says. As per current rates, a worker is supposed to get around ₹500 for cutting one tonne.

"These jobs were always fine in the first five months. Then, our employers would not give us wages daily. They would give us just ₹1,000 a week. We had to work even when we fell sick. They restricted our movements," he says.

Kotaiah says a policeman asked him to leave the employer during the pandemic. "But I told him that I owed my employer ₹2 lakh," he says. Kotaiah sold his house, received as part of a government scheme, for ₹1 lakh to clear the debt.

It was only when Kotaiah's friend died that he decided to leave. "We told our employer that we have to vote in the election (June 2024). He let us go. We never went back, despite warnings." This year, too, the employer created a ruckus in Alluru demanding that they all come back, he recalls. District officials of Prakasam intervened and gave the family protection and release certificates.

Venkateswarlu says that while the government hands out release certificates to survivors, the rehabilitation takes place so late in some cases that a few people, who find themselves without land and work after their release from bonded labour, go back to their old employers.

Today, Kotaiah lives in a spacious hut with a sofa, cot, and cooler. He says civil society members got him these necessities. Kotaiah sells fish for a living. "Some days, I get ₹200 and some days I make ₹400. Today I got only ₹100. But at least no one is torturing us," he says.

No action plan in place

"Apart from duck-rearing units, bonded labour cases are reported from areas where Subabul is grown extensively," says Ramesh, who belongs to the Rural Organisation for Poverty Eradication Services, a registered NGO.

In duck-rearing units, children are mostly chosen as labourers. "One has to be agile and quick to stop the ducks from escaping. Duck farmers, mostly Yerukulas (another Scheduled Tribe community), hire Yanadis to work for them. The conditions are harsh, with no electricity and no proper food," says Ramesh.

In his report 'Bonded Labour in India: Its Incidence and Pattern', former Jawaharlal Nehru University professor Ravi S. Srivastava says that the Supreme Court directed all the States to collect information on the prevalence of bonded labour in India. The survey was held in 1996. No cases were identified in Andhra Pradesh. However, the government subsequently identified and released 37,988 bonded labourers till 2004.

"Since then, no systematic survey has been carried out. Bonded labour persists both in the agricultural and non-agricultural sector, although vestiges of hereditary bondage only exist in traditional sectors," he says.

Of the 402 people who have been rescued in the past two years by the Vetti Vimochana Coalition, members say FIRs have been booked only in seven cases. "There is no Standard Operating Procedure or State action plan for the identification, rescue and rehabilitation of bonded labourers in Andhra Pradesh. On the other hand, States such as Tamil Nadu and Delhi have a robust system in place," explains Kumar.

While the Bonded Labour Act provides for punishment for up to three years, there is no data on how many people have been punished. The law mandates a district-level vigilance and monitoring committee to be in place. "This was formed in Prakasam only last year," Kumar says. Officials of the Revenue, Tribal Welfare, Social Welfare, and Labour Departments say they are not sure which of them is responsible for enforcing the Act.

"It is important to identify bonded labour as an organised crime," says Venkateswarlu. "The government should have a nodal department to deal with pre- and post-rescue operations. It should also have a toll-free number for people in distress. If there had been one, Ankamma would not have lost her son."

sravani@thehindu.co.in

Katti Kotaiah, 56, who also belongs to the Yanadi community, escaped the clutches of his employer at Chilakaluripeta town. Kotaiah and his wife Katti Gangamma (in the centre), depend on fishing for their livelihood these days. G.N. RAO

प्रमुख मुद्दे उजागर हुए:

1. बंधुआ मजदूरी का जारी रहना:

- बंधुआ मजदूरी, हालांकि गैरकानूनी है, लेकिन कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में जारी है, जिसमें बत्तख पालन और लकड़ी काटना शामिल है।
- वेंकटेश और उनके परिवार जैसे पीड़ित अक्सर गरीब, अशिक्षित, भूमिहीन और सामाजिक रूप से बहिष्कृत होते हैं - जो शोषणकारी श्रम प्रथाओं के क्लासिक पीड़ितों की प्रोफ़ाइल में फिट बैठते हैं।

2. कई कानूनों का उल्लंघन:

- इस मामले में कई कानूनों का उल्लंघन शामिल था, जिसमें बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम और अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत हत्या के आरोप शामिल हैं।
- हालाँकि, इन कानूनों का प्रवर्तन कमजोर है। दो वर्षों में आंध्र प्रदेश में बचाए गए 402 मामलों में से केवल 7 एफआईआर दर्ज की गईं।

3. बचाव और पुनर्वास तंत्र की अप्रभावीता:

- बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना (2021) 3 लाख रुपये तक के मुआवजे का वादा करती है, लेकिन व्यवहार में, राहत में देरी होती है या इनकार कर दिया जाता है, खासकर मरणोपरांत, जैसा कि वेंकटेश के मामले में हुआ।
- रिहाई प्रमाणपत्रों की कमी, खराब अंतर-विभागीय समन्वय और आंध्र प्रदेश में नोडल एजेंसी या मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपस्थिति प्रभावी प्रतिक्रिया में बाधा डालती है।

4. यानाडी समुदाय का हाशिए पर होना:

- कम साक्षरता और उच्च सामाजिक अलगाव के साथ यानाडी जनजाति गरीबी, कर्ज और बंधुआ मजदूरी के चक्र में फंसी हुई है।
- जमींदारों (रेड्डी की तरह) के प्रति सांस्कृतिक सम्मान, अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी और प्रतिशोध का डर उनके निरंतर शोषण में योगदान देता है।

5. प्रणालीगत अंतराल और जवाबदेही विफलताएँ:

- आंध्र प्रदेश में बंधुआ मजदूरी के पैमाने का आकलन करने के लिए कोई हालिया व्यापक सर्वेक्षण नहीं हुआ है।
- जिला स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियाँ या तो अनुपस्थित हैं या कार्यात्मक रूप से निष्क्रिय हैं, और सरकारी विभागों के बीच भूमिका संबंधी भ्रम बना हुआ है।

महत्वपूर्ण विश्लेषण:

- कानूनी ढाँचा बनाम जमीनी हकीकत: भारत में एक व्यापक कानूनी ढाँचा है, लेकिन इसका क्रियान्वयन खंडित है। पीड़ितों को अक्सर न्याय तक पहुँच की कमी होती है, और खराब निगरानी और अभियोजन के कारण शोषक दंड से बचकर काम करते हैं।

- अदृश्य और असंगठित शोषण: आज बंधुआ मज़दूरी वंशानुगत होने की तुलना में अधिक छिपी हुई है, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता है। शोषण अक्सर प्रवास, अनौपचारिक रोज़गार और अंतर-राज्यीय आवागमन से जुड़ा होता है, जिससे अधिकार क्षेत्र और बचाव प्रयास जटिल हो जाते हैं।
- संस्थागत तंत्र की आवश्यकता: समर्पित नोडल निकायों, प्रशिक्षित कर्मियों और वास्तविक समय की शिकायत तंत्र की अनुपस्थिति बंधुआ मज़दूरी के प्रति प्रतिक्रिया को कमज़ोर करती है। तमिलनाडु और दिल्ली जैसे राज्यों ने दिखाया है कि संस्थागत इच्छाशक्ति बदलाव ला सकती है।
- कानून से परे मानवीय त्रासदी: अंकम्मा जैसे परिवारों द्वारा झेले गए मनोवैज्ञानिक आघात, सामाजिक कलंक और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी ने पुनर्वास रणनीति की मांग की है जो मुआवजे से परे हो - आवास, शिक्षा, आजीविका और सम्मान पर ध्यान केंद्रित करे।

निष्कर्ष:

- वेंकटेश का मामला एक भयावह अनुस्मारक है कि भारत में बंधुआ मजदूरी अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के लिए एक जीवित वास्तविकता है। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, भारत को एक सुसंगत नीति, मजबूत प्रवर्तन, अंतर-राज्य समन्वय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से, बेजुबानों की रक्षा के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एक बच्चे की मौत केवल एक अलग सुर्खी नहीं होनी चाहिए - यह भारत में आधुनिक समय की गुलामी के पीड़ितों की पहचान करने, उन्हें बचाने और उनका पुनर्वास करने के तरीके में प्रणालीगत सुधार के लिए एक ट्रिगर होना चाहिए।

UPSC Mains Practice Questin

प्रश्न: कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद, भारत में बंधुआ मजदूरी जारी है, खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों में। इस प्रथा में योगदान देने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों की जांच करें और इसके उन्मूलन के लिए एक व्यापक रणनीति सुझाएँ। (250 wrds)

Page : 08 Editrial Analysis

Don't merely enrol students, but equip them with skills

Gourishankar S. Hiremath

Teaches Economics at IIT Kharagpur. Views are personal

As the admission season for colleges and universities begins, institutions across India are once again promoting their programmes under banners promising knowledge, transformation, and research excellence. This growth in enrolment at the undergraduate, postgraduate, and PhD levels suggests a dynamic academic landscape full of potential. Yet, beneath this expansion lies an important challenge: degrees are proliferating faster than meaningful job opportunities.

A gap that needs attention

According to data released by the Ministry of Statistics, the unemployment rate in India tends to increase with higher education levels. This paradox reveals a critical gap between academic achievement and employability – a gap that requires urgent attention.

This challenge is particularly acute in India's vast network of non-elite institutions in Tier 2 and tier 3 colleges, where most students pursue BA, BCom, or BSc degrees and their corresponding master's programmes. These institutions often face resource constraints and limited industry connections, operating with curricula that have not kept pace with the evolving job market. While elite colleges make headlines for placement challenges, the gradual erosion of employability in everyday colleges often goes unnoticed.

In many such institutions, instruction remains largely theoretical, with limited emphasis on real-world skills. For example, an English literature student might study Shakespearean tragedy yet miss out on learning practical skills such as writing professional emails. Similarly, an economics graduate may understand complex theories but struggle with everyday tools such as Excel. This disconnect means millions of educated young people find it difficult to translate their degrees into career opportunities.

This situation stems partly from a deeply entrenched academic culture that values scholarship and abstraction over practical application. Within many academic circles – even prestigious ones – higher education is often celebrated as an end in itself, while immediate employment is sometimes subtly undervalued. Postgraduate degrees and PhDs are frequently pursued not just for intellectual fulfilment but as a refuge from the job market, creating a cycle where many graduates end up teaching in the very colleges that perpetuate the same system.

It is important to recognise that successive governments have acknowledged this issue. Initiatives such as Skill India, Start-Up India, and the National Education Policy have pushed for skill development, vocational training, and entrepreneurship. However, the transformation remains incomplete. Many undergraduate and postgraduate programmes continue to emphasise rote learning over practical skills. While new courses in AI or entrepreneurship are being introduced, they often lack depth, and integration into the broader curriculum.

A broader societal challenge

Countries such as China and Japan have successfully aligned education with economic strategies by elevating technical and vocational education to a central role in workforce development. In India, vocational training is still often perceived as a fallback option, both within academia and society. This stigma limits the appeal and effectiveness of skill-based education, despite its vital role in economic empowerment.

This contradiction highlights a broader societal challenge: degrees are highly valued as symbols of upward mobility, but they increasingly fail to guarantee it. This is not a call to abandon liberal education or abstract learning – they remain essential for critical thinking and creativity. However, education must also provide tangible economic benefits. Degrees should offer pathways to agency and dignity, especially for students from smaller towns and under-resourced institutions.

A way forward lies in integrating practical skill modules – communication, digital literacy, budgeting, data analysis, hospitality, tailoring, and health services – into general degree programmes as core elements, not optional extras. Doctoral education should be diversified to prepare candidates for policy, analytics, consulting, development, and industry roles, not solely academia. Research remains vital, but it must be pursued by those inclined towards it.

Finally, the widespread aspiration for government jobs reflects the limited opportunities graduates currently perceive. While these roles remain important, expanding private sector and entrepreneurial pathways through improved employability will offer youth a broader range of options. Enhancing skills and opportunities can reduce the over-dependence on competitive exams. India's growing economy demands an education system that not just enrols students, but equips students with skills. Viewing education as a social contract that guarantees a meaningful connection between learning and livelihood is essential.

Viewing education as a social contract that guarantees a meaningful connection between learning and livelihood is essential

Paper 02 : शासन एवं सामाजिक न्याय

UPSC Mains Practice Question : भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली में नामांकन में वृद्धि देखी जा रही है, फिर भी रोजगार की संभावना एक बड़ी चिंता बनी हुई है। इस विरोधाभास के कारणों की आलोचनात्मक जांच करें और शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के उपाय सुझाएँ। (250 words)

संदर्भ:

- भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ने के साथ ही एक विरोधाभासी प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है - शिक्षित लोगों में बेरोजगारी की दर अक्सर अधिक होती है, खासकर स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री वाले लोगों में। आईआईटी खड़गपुर

के एक शिक्षाविद द्वारा की गई यह टिप्पणी अकादमिक शिक्षा और रोजगार की तैयारी के बीच बढ़ते वियोग को उजागर करती है, खासकर गैर-कुलीन टियर 2 और टियर 3 संस्थानों में, जहां अधिकांश भारतीय छात्र पढ़ते हैं।

मुख्य मुद्दे उजागर किए गए:

1. शिक्षा-रोजगार वियोग:

- वर्तमान प्रणाली कौशल की तुलना में डिग्री को प्राथमिकता देती है, पारंपरिक पाठ्यक्रम वास्तविक दुनिया की नौकरी की आवश्यकताओं के साथ संरेखण की कमी रखते हैं।
- छात्र, शैक्षणिक उपलब्धियों के बावजूद, अक्सर बुनियादी कार्यस्थल उपकरणों (जैसे, एक्सेल, संचार, बजट) के साथ संघर्ष करते हैं, खासकर सामान्य डिग्री कार्यक्रमों (बीए, बीकॉम, बीएससी) में।

2. व्यावहारिकता पर सैद्धांतिक ध्यान:

- उच्च शिक्षा अमूर्तता, सिद्धांत और रटने वाली शिक्षा पर केंद्रित है, जो व्यावसायिक प्रासंगिकता और व्यावहारिक अनुप्रयोग को कम महत्व देती है।
- स्नातकोत्तर शिक्षा को अक्सर नौकरी के बाजार से बचने के लिए अपनाया जाता है, जो बदले में उसी पुरानी शैक्षणिक संस्कृति को पुनरुत्पादित करता है।

3. असमान सुधार कार्यान्वयन:

- कौशल भारत, स्टार्ट-अप इंडिया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) जैसी सरकारी पहलों ने सुधार का प्रयास किया है, लेकिन क्रियान्वयन में कमी आई है।
- एआई या उद्यमिता में नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं, लेकिन उनमें एकीकरण और व्यावहारिक गहराई का अभाव है।

4. व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में सामाजिक कलंक:

- जापान और चीन जैसे देशों के विपरीत, भारत व्यावसायिक प्रशिक्षण को हीन या एक विकल्प के रूप में देखता है, जो इसे मुख्यधारा में अपनाने को सीमित करता है।
- यह सांस्कृतिक मानसिकता रोजगार-आधारित शिक्षा की ओर संरचनात्मक बदलाव को रोकती है।

5. समावेशी कौशल एकीकरण की आवश्यकता:

- संचार, डिजिटल साक्षरता, डेटा विश्लेषण, वित्तीय कौशल और उद्यमिता को मुख्य घटकों के रूप में सामान्य डिग्री कार्यक्रमों में शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है।
- छात्रों को नीति, परामर्श, विकास और निजी क्षेत्रों में गैर-शैक्षणिक करियर के लिए तैयार करने के लिए पीएचडी प्रशिक्षण में विविधता लाई जानी चाहिए।

6. सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता:

- प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों पर सीमित ध्यान निजी क्षेत्र के सीमित मार्गों और खराब रोजगार क्षमता का लक्षण है।
- कौशल के साथ छात्रों को सशक्त बनाने से सरकारी नौकरियों पर अत्यधिक निर्भरता कम होगी और आजीविका के विकल्प बढ़ेंगे।

आलोचनात्मक विश्लेषण:

- डिग्री बनाम क्षमताएँ: औपचारिक डिग्री के प्रति जुनून ने कार्यात्मक और हस्तांतरणीय कौशल की आवश्यकता को कम कर दिया है। एक शिक्षा प्रणाली जो आर्थिक एजेंसी प्रदान करने में विफल रहती है, वह सामाजिक रूप से प्रतिगामी बनने का जोखिम उठाती है, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए।
- गैर-अभिजात वर्ग के संस्थानों की भूमिका: अधिकांश छात्र साधारण कॉलेजों में पढ़ते हैं, जिनमें फंडिंग, उद्योग संबंध और अद्यतन पाठ्यक्रम की कमी होती है। किसी भी सुधार को संकाय प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम में सुधार और संस्थागत-उद्योग साझेदारी के माध्यम से इन संस्थानों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- शिक्षा को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में फिर से परिभाषित करना: शिक्षा को एक प्रमाणन अभ्यास से गरिमा और आजीविका को सुरक्षित करने के साधन में बदलना चाहिए। इसके लिए पारंपरिक डिग्री से परे विविध शिक्षण पथों की नीति-स्तरीय प्रतिबद्धता और सामाजिक स्वीकृति की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली एक चौराहे पर है। नामांकन बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार की संभावना स्थिर बनी हुई है। अगर शिक्षा को वास्तव में परिवर्तनकारी होना है, तो उसे छात्रों को केवल अकादमिक डिग्री ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक कौशल प्रदान करके सीखने-जीने के बीच के अंतर को पाटना होगा। सुधार समावेशी, कौशल-केंद्रित और सामाजिक रूप से सशक्त होना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो कम संसाधन वाले क्षेत्रों में रहते हैं। तभी भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय लाभ बन सकता है।